उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 13 जून, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(06/75)

राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल के लिये प्रतिबद्ध है : मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 3200 करोड़ के 594 प्रपोजल्स स्वीकृत किए गए, इसके मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018–19 के मात्र 2 माह में 2.5 हजार करोड़ 92 इन्वेस्टमेंट स्वीकृत।**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार को देहरादून के स्थानीय होटल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित "मुख्यमंत्री के साथ बातचीत" कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि राज्य में इन्वेस्टर्स को दोस्ताना माहौल उपलब्ध करा सकें। सरकार इन्वेस्टर्स को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। राज्य उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है पर अभी इसमें और मैच्योरिटी की आवश्यकता है। सीआईआई हमेशा से राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में लीडर्स स्टेट्स की श्रेणी में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उद्योग के क्षेत्र में लीडर्स स्टेट की प्रमुख श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए 10 करोड़ तक की स्वीकृति देने के लिए जिलाधिकारियों को अनुमति दे दी है। उद्योग के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू है, जो निश्चित रूप से सिंगल विंडो सिस्टम से इन्वेस्टर्स को लाभ मिलेगा। अक्टूबर माह में इन्वेस्टर्स मीट भी प्रस्तावित है, जो निश्चित रूप से इंवेस्टर्स को आकर्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैविक खेती के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म नीति में परिवर्तन करते हुए यहां शूटिंग को फ्री किया है। आप बहुत से फिल्म प्रोजेक्ट्स यहां शुरू हो रहे हैं शीघ्र ही यहां दक्षिण भारत की फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है। फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलने से स्थानीय व्यापारियों होटल व्यवसायियों एवं कलाकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शूटिंग साइट्स के क्षेत्र में भी उत्तराखंड में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे होटल्स की आवश्यकता है। अच्छे होटल्स बनाने में सीआईआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने सीआईआई का आह्वान करते हुए कहा कि हम सब मिलकर उत्तराखंड के विकास में सहयोग करें।

प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पवार ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है।उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम को सरलतम बनाया जाए। सरकार लगातार इस सिंगल विंडो सिस्टम को सरलतम बनाने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 3200 करोड़ के 594 प्रपोजल्स स्वीकृत किए गए, इसके मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018–19 के मात्र 2 माह में 2.5 हजार करोड़ 92 इन्वेस्टमेंट स्वीकृत किए हैं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 13 जून, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(06/74)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रख्यात चित्रकार श्री सुरेन्द्र पाल जोशी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा उनके परिजनों को दुःख की इस घड़ी में सांत्वना प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द ने स्व.जोशी के निधन को राज्य के कला जगत के लिये अपूरणीय क्षति बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व.सुरेन्द्र पाल जोशी के मार्गदर्शन में घंटाघर स्थित हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा काम्पलेक्स में उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह संग्रहालय उनकी स्मृतियों को सदैव संजोए रखेगा। ज्ञातव्य है कि स्व.जोशी की अस्वस्थता के दौरान उनके उपचार के लिये मुख्यमंत्री द्वारा 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 13 जून, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(06/73)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन से सम्बन्धित जिन विभागों के जो भी प्रकरण लम्बित हैं, ऐसे सभी तथ्यों एवं प्रकरणों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाय, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ आगामी बैठक में सभी मामलों पर गहन विचार–विमर्श कर समाधान निकाला जा सके।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लम्बित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दोनों राज्यों के मध्य परिसम्पतियों के हस्तांरण के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की दिशा में सहमति व्यक्त कर चुके है। अतः इस सम्बन्ध में सभी प्रकरणों की व्यापक रूप से समीक्षा कर ली जाय, ताकि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आगामी जुलाई माह मे होने वाली सम्भावित बैठक में राज्य से जुड़ी आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के प्रकरणों पर अन्तिम निर्णय लेकर उनका स्थायी समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द ने यह भी निर्देश दिये है कि परिसम्पतियों के वितरण से सम्बन्धित जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है उन पर भी दोनों राज्य की आपसी सहमति के प्रयास किये जाय ताकि उनका भी समाधान शीघ्रता से हो सके।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वर्ष 2011 के पश्चात उ0प्र0 से पेंशन की मद में प्राप्त होने वाली धनराशि का मसला उ0प्र0 के व उत्तराखण्ड के महालेखाकारों के स्तर पर निस्तारित होना है। इस सम्बन्ध में भी माह जुलाई में एक बैठक पृथक से दोनो राज्यों के महालेखाकारों एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित करा ली जाय। उन्होंने मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना के लिये एलआईसी से प्राप्त ऋण के समाधान तथा टीएचडीसी से 25 प्रतिशत शेयर उत्तराखण्ड को दिये जाने व विभिन्न विभागों से सम्बन्धित ब्याज की धनराशि के समाधान के लिये प्रकरण भारत सरकार को पुनः सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही बैराजों के विद्युत बिलों के भुगतान तथा कर्मचारियों के पीएफ से सम्बन्धित धनराशि का भी आकलन कर विवरण तैयार करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये, ताकि इस मसलों का हल भी उत्तर प्रदेश के साथ आगामी बैठक में निकाला जा सके।

दोनों राज्यों के मध्य ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन, पर्यटन, खाद्य एवं आपूर्ति, वन निगम, वित्त, औद्योगिक विभाग, आवास विकास विभाग से सम्बन्धित विभिन्न मसलों पर आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन होना है। जिनका विभागवार विवरण तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव वित्त श्री अमित सिंह नेगी, सचिव परिवहन श्री डी. सेंथिल पाण्डियन एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून 13 जून, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(06/72)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के लोक कलाकार स्वर्गीय पप्पू कार्की के परिवारजनों को 05 लाख रु. की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। यह राशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय कार्की की मृत्यु लोककला के लिये अपूरणीय क्षति है।

देहरादून 13 जून, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(06/71)**

फिल्म निर्देशक श्री नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री से की भेंट

- **फिल्म '' बत्ती गुल मीटर चालू'' के लिए राज्य के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्देशक श्री नारायण सिंह ने भेंट। फिल्म निर्देशक श्री नारायण सिंह ने फिल्म *''बत्ती गुल मीटर चालू''* की टिहरी में सूटिंग के लिए राज्य सरकार के अच्छे सहयोग पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। फिल्म *''बत्ती गुल मीटर चालू''* 31 अगस्त 2018 को रिलीज होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं में प्रतिभाएं बहुत हैं, उन्हें अवसर देने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड का वातावरण एवं प्राकृतिक सौंदर्य फिल्म की सूटिंग के लिए अनुकूल है। ऑल वेदर रोड बनने के बाद प्रदेश में कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा से फिल्म सूटिंग के लिए प्रदेश में और अधिक अवसर बढ़ेंगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। फिल्म जगत के सभी लोगों को प्रदेश में फिल्मांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा भरपूर सहयोग दिया जायेगा। फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सूटिंग का शुल्क पूर्ण रूप से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ''13 डिस्ट्रिक 13 न्यू डेस्टिनेशन'' की राज्य सरकार की परिकल्पना है। प्रत्येक जिले में एक–एक डेस्टिनेशन का चयन कर विकसित किया जा रहा है।

इस अवसर पर प्रोड्यूसर श्री नितिन चन्द्रचूड, श्री रति शंकर त्रिपाठी, श्री सुमित अद्लखा एवं श्री प्रमोद राणा उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 13 जून, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(06/70)

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना–2022 तक सबके लिए आवास योजना की समीक्षा की। बुधवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय स्वीकृति और मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने लाभार्थी तक जल्द लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2022 तक हर हाल में प्रदेश में हर बेघर को घर मुहैया कराना है। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक कि प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। कहा कि 104971 आवास की मांग राज्य में है। अभी तक 16125 आवासों के निर्माण किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आवास विभाग एमआईएस को और अधिक मजबूत करे। मॉनिटरिंग की व्यवस्था हर स्तर पर की जाय। नगर निकायों के अधिकारियों और स्टाफ की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराई जाय।

बैठक में सचिव आवास श्री आर.के.सुधांशू ने बताया कि लाभार्थी आधारित निर्माण योजना के अंतर्गत 14898 आवास बनाये जाने हैं। जिनके पास 30 वर्ग मीटर की जमीन है उसे 2 लाख रुपये की सब्सिडी मकान बनाने के लिए दी जाएगी। अब तक 11860 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। भागीदारी में किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) के तहत 38472 आवास बनाये जाने हैं। इसके तहत जिनके पास जमीन नही है और किराये के मकान में रह रहा हो, उसे 30 वर्ग मीटर के आवास हेतु 2.50 लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 2864 लोगों को लाभ दिया गया है। ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास (क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम) के अंतर्गत 14248 आवास बनाये जाने हैं। इसमें आवास विहीन परिवारों को कम ब्याज दर पर बैंक से 30 वर्ग मीटर से 150 वर्ग मीटर तक आवास हेतु 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक ऋण हेतु ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम में 1401 लोगों को लाभ दिया गया है।

समिति ने बीएलसी घटक के अंतर्गत 14 नगर निकायों से प्राप्त 885 आवासों के निर्माण का अनुमोदन दिया। ये आवास कपकोट, डोईवाला, मंगलोर, कोटद्वार, बड़कोट, नौगांव, चिन्यालीसौड़, पोखरी, हल्द्वानी, नानकमत्ता, बाजपुर, बेरीनाग, चंपावत और किच्छा में बनाये जाएंगे। समिति ने एमडीडीए को धौलास और उत्तर आवासीय योजना में 1108 साझेदारी में किफायती आवास बनाने का अनुमोदन दिया।

बैठक में अपर सचिव श्री भूपाल सिंह मनराल, श्री सुनिलश्री पांथरी, वीसी एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव, वीसी एचडीए श्री नितिन भदौरिया, सचिव श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग